



छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण) प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 697]

नवा रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 29 अगस्त 2025 — भाद्र 7 शक 1947

महिला एवं बाल विकास विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर

नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक 29 अगस्त 2025

अधिसूचना

क्रमांक एफ 12-4/2020/मबावि/50.— किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2015 यथा संशोधित 2021 की धारा 04 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये तथा राज्य स्तरीय चयन समिति की अनुशंसा के अनुसार राज्य सरकार एतद्वारा नीचे लिखे तालिका के कॉलम क्रमांक (3) में उल्लेखित व्यक्तियों को कॉलम क्रमांक (2) में उल्लेखित तत्संबंधी जिले के किशोर न्याय बोर्ड में सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में, नीचे उल्लेखित शर्तों के अध्याधीन रहते हुये, नियुक्त करती है, अर्थात्:-

क्र.	जिला	किशोर न्याय बोर्ड के सदस्य का नाम
1.	बलरामपुर 01 सामाजिक कार्यकर्ता (01 महिला)	श्रीमती रश्मि गुप्ता, श्री शैलेश कुमार गुप्ता
2.	बस्तर 01 सामाजिक कार्यकर्ता (01 महिला)	श्रीमती हेमलता देवांगन, श्री सुनील कुमार देवांगन
3.	बीजापुर 01 सामाजिक कार्यकर्ता	श्री दशरथ कुमार तामडी, स्व. श्री रामलू
4.	दंतेवाड़ा 01 सामाजिक कार्यकर्ता	डॉ. निर्मला साहू, श्री गणेश राम साहू
5.	नारायणपुर 01 सामाजिक कार्यकर्ता	कु. मलनी बघेल, स्व. श्री बलिहार बघेल
6.	रायगढ़ 02. सामाजिक कार्यकर्ता (01 महिला)	1. श्रीमती विनीता अग्रवाल, श्री संजय कुमार अग्रवाल 2. श्री गेंद सिंह चन्द्रा, श्री टी.आर.चन्द्रा
7.	रायपुर 01 सामाजिक कार्यकर्ता (01 महिला)	श्रीमती करुणा सिंगी, श्री राजेश सिंग
8.	गरियाबंद 01 सामाजिक कार्यकर्ता	श्रीमती केमेश्वरी साहू, श्री तेनसिंह साहू

शर्तें:-

- (1) यह नियुक्तियां अभ्यर्थियों द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र एवं व्यक्तिगत वार्तालाप में दी गई जानकारी तथा उपलब्ध कराये गये दस्तावेजों के आधार पर की गई है। किसी भी स्तर पर गलत जानकारी या विसंगति अथवा शिकायत की दशा में राज्य शासन को संबंधित व्यक्ति की नियुक्ति निरस्त करने का अधिकार होगा। इस संबंध में कोई अभ्यावेदन स्वीकार्य नहीं होगा।
- (2) किशोर न्याय बोर्ड के सामाजिक कार्यकर्ताओं की पदावधि, इस आदेश के जारी होने के दिनांक से तीन वर्ष की कालावधि के लिये होगी। नियुक्त अध्यक्ष/सदस्य की आयु जिस दिन 65 वर्ष पूर्ण होगी उस दिन नियुक्ति स्वमेव समाप्त हो जावेगी।

- (3) बोर्ड, बाल संप्रेक्षण गृह के परिसर में या जिला बाल संरक्षण समिति द्वारा विनिश्चित स्थान पर अपना बैठक आहूत करेगा, जिसमें विहित तिथि/समय पर अध्यक्ष/सदस्य की उपस्थिति अनिवार्य होगी।
- (4) किशोर न्याय बोर्ड के सामाजिक कार्यकर्ताओं की नियुक्ति, किशोर न्याय(बालकों की देखरेख एवं संरक्षण) अधिनियम 2015 यथा संशोधित 2021 की धारा (4) की उपधारा (7) के प्रावधानों के अनुसार समाप्त की जा सकेगी।
- (5) किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) नियम, 2016 यथा संशोधित 2022 के नियम 5(3) अनुसार बोर्ड के सामाजिक कार्यकर्ताओं राज्य सरकार को एक माह का लिखित नोटिस देकर त्याग पत्र दे सकेंगे।
- (6) नियुक्त सामाजिक कार्यकर्ता किशोर न्याय (बालकों की देखरेख एवं संरक्षण अधिनियम, 2015 यथा संशोधित 2021 तथा किशोर न्याय (बालकों की देखरेख एवं संरक्षण) नियम, 2016 यथा संशोधित 2022 के प्रावधानों के अनुसार कार्य करेंगे।
- (7) यदि नियुक्त सामाजिक कार्यकर्ता, किसी ऐसे व्यवसाय/सेवा में है, जो किशोर न्याय बोर्ड के सदस्य के रूप में उनके कार्यों को प्रभावित कर सकते हैं, तो उन्हें अपनी वर्तमान सेवा/व्यवसाय का कार्य अनिवार्य रूप से स्थगित करना होगा एवं इस आशय का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।
- (8) किशोर न्याय बोर्ड में नियुक्त सामाजिक कार्यकर्ता यदि अधिवक्ता है, तो बोर्ड में अपने कार्यकाल के दौरान प्रेक्टिस नहीं करेंगे तथा इस हेतु उन्हें किशोर न्याय बोर्ड में अपने कार्यकाल की अवधि तक छत्तीसगढ़ राज्य अधिवक्ता परिषद् से अपना पंजीयन/सनद् स्थगित कराना होगा तथा उन्हें इस संबंध में सुसंगत दस्तावेज विभाग को उपलब्ध कराना होगा। इसके पश्चात ही वे किशोर न्याय बोर्ड में उपस्थिति दे सकेंगे।
- (9) यह नियुक्ति पुलिस सत्यापन होने तक प्रावधिक मानी जायेगी। यदि किसी नियुक्त अभ्यर्थी के पुलिस सत्यापन में विपरीत टीप प्राप्त होती है, तो उसकी नियुक्ति तत्काल प्रभाव से समाप्त मानी जायेगी।
- (10) नियुक्ति आदेश जारी होने के 15 दिवस के भीतर संबंधित जिले में उपस्थिति दिया जाना अनिवार्य होगा। जिले में उपस्थिति के समय समस्त आवश्यक दस्तावेज जमा करना होगा।
- (11) नियुक्त सामाजिक कार्यकर्ता को किशोर न्याय (बालकों की देखरेख एवं संरक्षण) नियम, 2016 यथा संशोधित 2022 के नियम 89(3) अनुसार प्रशिक्षण लेना अनिवार्य होगा।
- (12) माननीय उच्च न्यायालय में विचाराधीन प्रकरण WPS क्रमांक 4536/2024 के परिपेक्ष्य में सामाजिक कार्यकर्ता किशोर न्याय बोर्ड, कांकर में की गयी नियुक्ति माननीय उच्च न्यायालय द्वारा प्रकरण में लिये गये निर्णय के अध्वधीन होगी।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
शम्मी आबिदी, सचिव.

नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक 29 अगस्त 2025

अधिसूचना

क्रमांक एफ 12-4/2020/मबावि/50.— किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2015 यथा संशोधित 2021 की धारा 27 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये तथा बालक कल्याण समिति के अध्यक्ष/सदस्यों के चयन के लिये गठित राज्य स्तरीय चयन समिति की अनुशंसा के अनुसार, राज्य सरकार, एतद्वारा, नीचे उल्लेखित तालिका के कॉलम क्रमांक (3) में उल्लेखित व्यक्तियों को कॉलम क्रमांक (2) में उल्लेखित तत्संबंधी जिले के बालक कल्याण समिति में, क्रमशः अध्यक्ष/सदस्य के रूप में, नीचे उल्लेखित शर्तों के अध्याधीन रहते हुये, नियुक्त करती है, अर्थात:-

क्र.	जिला	बाल कल्याण समिति के अध्यक्ष का नाम
1.	2.	3.
1.	बलरामपुर	श्री कमलेश सिंह परमार श्री रामाधार सिंह
2.	बीजापुर	श्री मिथलेश कुमार मंचारला, स्व. श्री एम. वेंकट स्वामी
3.	कोण्डागांव	श्री त्रिलोक राम, स्व. श्री जगत राम
4.	कोरबा	श्री उत्तम कुमार पाठक, स्व. श्री रामकपिल पाठक
5.	नारायणपुर	श्रीमती पूनम देवांगन, श्री देवेन्द्र देवांगन
	जिला	बाल कल्याण समिति के सदस्यों का नाम
1.	बलरामपुर 02 सदस्य	1. श्री राजकुमार सिंह यादव, स्व. श्री भागवत प्रसाद यादव 2. श्रीमती निर्मला जांगड़े, श्री नर्मदा प्रसाद जांगड़े
2.	बीजापुर 01 सदस्य	श्रीमती देविन्दा राना, श्री नंद किशोर राना
3.	दंतेवाड़ा 02 सदस्य	1. श्रीमती ज्योत्सना बारई, श्री उमेश चन्द्र बारई 2. श्रीमती जानकी साहू, श्री छत्र कुमार साहू
4.	धमतरी 01 सदस्य	1. श्रीमती सरोज देवांगन, श्री संतोष देवांगन
5.	कांकेर 01 सदस्य	श्री अवधेश लारिया, श्री एस.डी.लारिया
6.	कोण्डागांव 01 सदस्य (महिला)	1. श्रीमती प्रतिमा मिश्रा, स्व. श्री हेमन्त मिश्रा
7.	कोरिया 01 सदस्य	1. श्री कृष्णकान्त मिश्रा, श्री चन्द्रमोहन मिश्रा
8.	मुंगेली 02 सदस्य	1. श्री रमेश कुमार कुलमित्र, श्री मिला लाल कुलमित्र 2. श्री रविशंकर साहू, श्री लाल जी साहू
9.	नारायणपुर 02 सदस्य	1. श्री शमन कुमार मांझी, स्व. श्री मेहत्तर राम मांझी 2. श्री अनुसूईया नेताम, श्री हिरामन नेताम

शर्तें:-

- (1) यह नियुक्तियां अभ्यर्थियों द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र एवं व्यक्तिगत वार्तालाप में दी गई जानकारी तथा उपलब्ध कराये गये दस्तावेजों के आधार पर की गई है। किसी भी स्तर पर गलत जानकारी या विसंगति अथवा शिकायत की दशा में राज्य शासन को संबंधित व्यक्ति की नियुक्ति निरस्त करने का अधिकार होगा। इस संबंध में कोई अभ्यावेदन स्वीकार्य नहीं होगा।
- (2) बालक कल्याण समिति के अध्यक्ष/सदस्यों की पदावधि, इस आदेश के जारी होने के दिनांक से तीन वर्ष की कालावधि के लिये होगी। नियुक्त अध्यक्ष/सदस्य की आयु जिस दिन 65 वर्ष पूर्ण होगी उस दिन नियुक्ति स्वमेव समाप्त हो जावेगी।
- (3) बालक कल्याण समिति, किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम 2015 यथा संशोधित 2021 की धारा 28 की उप-धारा (1) के अनुसार अपनी बैठक आहूत करेगी, जिसमें विहित तिथि/समय पर अध्यक्ष/सदस्य की उपस्थिति अनिवार्य होगी।
- (4) बालक कल्याण समिति, बाल गृह के परिसर में या जिला बाल संरक्षण इकाई द्वारा विनिश्चित स्थान पर अपनी बैठक आहूत करेगी।
- (5) बालक कल्याण समिति के सदस्यों की नियुक्ति, किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2015 यथा संशोधित 2021 की धारा (27) की उप-धारा (7) के प्रावधानों के अनुसार समाप्त की जा सकेगी।
- (6) किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) नियम 2016 यथा संशोधित 2022 के नियम 15(6) अनुसार समिति के अध्यक्ष/सदस्य राज्य सरकार को एक माह का लिखित नोटिस देकर त्यागपत्र दे सकेंगे।
- (7) समिति, किशोर न्याय (बालकों की देखरेख एवं संरक्षण) अधिनियम, 2015 यथा संशोधित 2021 तथा किशोर न्याय (बालकों की देखरेख एवं संरक्षण) नियम, 2016 यथा संशोधित 2022 के अनुसार बालकों के कल्याण एवं संरक्षण के लिये कार्य करेंगी।
- (8) यदि नियुक्त अध्यक्ष/सदस्य, किसी ऐसे व्यवसाय/सेवा में है, जो बालक कल्याण समिति के सदस्य के रूप में उनके कार्यों को प्रभावित कर सकते हैं, तो उन्हें अपनी वर्तमान सेवा/व्यवसाय का कार्य स्थगित करना होगा, एवं इस आशय का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।
- (9) यह नियुक्ति पुलिस सत्यापन होने तक प्रावधिक मानी जायेगी। यदि किसी नियुक्त अभ्यर्थी के पुलिस सत्यापन में विपरीत टीप प्राप्त होती है, तो उसकी नियुक्ति तत्काल प्रभाव से समाप्त मानी जायेगी।
- (10) नियुक्ति आदेश जारी होने के 15 दिवस के भीतर संबंधित जिले में उपस्थिति दिया जाना अनिवार्य होगा। जिले में उपस्थिति के समय समस्त आवश्यक दस्तावेज एवं फार्म 49 में शपथ पत्र जमा करना होगा।
- (11) नियुक्त अध्यक्ष/सदस्य को किशोर न्याय (बालकों की देखरेख एवं संरक्षण) नियम, 2016 यथा संशोधित 2022 के नियम 89(3) अनुसार प्रशिक्षण लेना अनिवार्य होगा।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
शम्मी आबिदी, सचिव.